provisions for migrants Rs. 8 crores. In regard to security and law and order a provision of Rs. 80 crores has been made in the current year's Budget.

A question has been asked alleging discrimination between Jammu and Kashmir regions. There is no discrimination whatsoever made in the Budget proposals between Jammu region on the one hand, and Kashmir valley on the other. In fact, the Government of India is committed to removal of regional imbalances and the Budget provisions have been made keeping that in view. Besides these two regions the State also consists of Ladakh region which is also receiving due attention of the Government.

With these words, Sir, I request this honourable House to take the Bill into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The question is:

"That the Bill to authorise payment and and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 1991-92, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Sir I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JAGESH DESAI: Sir, I would like to make a suggestion. Before we take up the second Bill, we would like the Prime Minister to make his statement on the five diamond merchant who were kidnapped. We are anxious to know as to what has happened.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): No, let us pass the Bill first.... *(Interruptions)*

SHRI VIREN J. SHAH: Let us finish the legislative business first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The consensus of the House is that the Bill should be taken up first.

THE ELECTRICITY LAWS (AMENDMENT, BILL, 1991

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

विद्युत की लगातार मांग और संसाधनों की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा इस क्षेत्र में अपना समुचित योगदान दिए जाने को ध्यान में रखते हुए विद्युत में निजी क्षेत्र निवेश को तत्साहित कए जाने के माध्य से विद्युत उत्प दन सप्लाई एवं वितरण क्षम। संवर्धन किए जाने संबंधी कार्यक्रम हेतु संसाधनों में बढ़ोत्तरी किये जाने संबंध नीति के बारे में सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से विचार किया जाता रहा है जून, 1988 में, तत्कालीन सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इस समय, कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में निजी क्षेत्र का केवल 4 प्रतिशत का योगदान है। यद्यपि विद्युत की सप्लाई एवं वितरण हेतु 57 वितरण कम्पनियों को लाइसें दिया गया है, तथापि अब तक नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र के विद्यमान लाइसेंसधारियों को केवल क्षमता-संवर्द्धन और क्षमता-प्रतिस्थापन हु अनमति दी जाती रही है। संसाधनोंमें

[श्री कल्पनाथ राय]

वृद्धि किए जाने संबंधी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नई नीति तैयार की गई है जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश की भागीदारी को और अधिक व्यापक बनाया गया है ।

नई नीति में, निजी क्षेत्र की यूनिटों के लिए और अधिक उदार आर्थिक अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान है और इस नीति के संघटकों में ये शामिल हैं :—

लाइसेंसधारी कंपनियों अर्थात विद्युत की सप्लाई एवं वितरण करने वाली कंपनियों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों का प्रावधान है :—

(1) वर्तमान में लाइसेंस की 20 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि तथा उसके बाद 10 वर्ष की नवीकरण अवधि को बढ़ाकर क्रमशः 30 वर्ष तथा 20 वर्ष करना ।

(2) इस समय विद्यमान 2 प्रतिशत लाभांश दर को बढ़ाकर भारतीय रिजर्व बैंक की दर से 5 प्रतिशत अधिक करना ।

(3) निर्माण के दौरान ब्याज (आई. डी.सी.) का पंजीकरण, वास्तविक लागत पर करना जबकि इस समय यह रिजर्व बैंक की दर से एक प्रतिशत अधिक दर पर किया जाता है । और

(4) ऋण संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के लिए विशेष विनियोजन ।

इसके अलावा लाइसेंसधारी कम्पनियों को केवल परिवर्धनों अथवा प्रतिस्थापन हेतु अनुमति संबंधी नीति के स्थान पर अब नये लाइसेंसों पर विचार किया जायेगा ।

निजी क्षेत्र उद्यमी, चाहे वे लाइसेंसधारी नहीं हैं, अब विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापित कर सकते हैं जो कि अब केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या दोनों द्वारा स्थापित की जा सकती थी । इस प्रकार की विद्युत उत्पादन कम्पनियों को सरकार द्वारा निर्धारित नारमेटिव पैरामीटर्स पर आधारित लाभकारी कीमत पर ग्रिड के लिए विद्युत की बिक्री किये जाने की अनुमति दी जायेगी, इससे प्रचालन कार्य अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा ।

निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं के आकार एवं स्वरूप के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं होगा । दूसरे शब्दों में, निजी क्षेत्र द्वारा अब किसी भी साइज और क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं (कोयला/लिग्नाइट या गैस आधारित), जल विद्युत परियोजनाओं, पवन/सौर ऊर्जा और डी.जी. सेट परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है । नयी नीति में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा स्वीकृति दिये जाने के संदर्भ में 5 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है और इसे ज्यादा लचीला बनाय गया है ।

जबकि उपर्युक्त प्रावधानों के लिए बिजली कानूनों में संशोधन किया जाना अपेक्षित होगा, नयी नीति के अन्तर्गत कानूनी उपायों के साथ-साथ प्रशासनिक उपाय किये जाने का प्रावधान है । विद्युत क्षेत्र के सभी निजी क्षेत्र यूनिटों के लिये 4 : 1 तक के ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति दी जायेगी । जहां तक विदेशी निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किये जाने का संबंध है, एक उदार विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जायेगी । निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली नई उपस्कर के आयात की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते वित्तीय पैक्स सरकार को स्वीकार्य हो । इसके अलावा नई नीति के अन्तर्गत, विद्युत परियोजनाओं के संबंध में शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सिंगल प्वाइंट क्लीयरेंस प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रावधान है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को शामिल करते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसमें राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोजित किया जाएगा । इस बोर्ड के अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होंगे । बोर्ड द्वारा सांविधिक स्वीकृतियों की मानिटरिंग क

जाएगी और इस संबंध में लम्बित मामलों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हल किया जाएगा । परियोजनाओं, स्वीकृतियों संबंधी मोडेलिटीज आदि के बारे में उद्यमियों को सूचना प्रदान करने एवं उनकी सहायता करने और उनके प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिये नोडल मंत्रालय अर्थात् विद्युत विभाग में एक निवेश प्रोत्साहन सेल (आई० पी०सेल०) को क्रियाशील बनाया गया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस नीति को कार्यरूप देने के लिये भारतीय बिजली अधिनियम–1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम–1948 में संशोधन किये जाने अपेक्षित होंगे । विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक–1991 में ये संशोधन निहित हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि इन संशोधनों के संबंध में राज्य सरकारों ने अपनी सहमति व्यक्त की है । 6–9–1991 को हुये राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा न केवल नयी नीति और विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक, 1991 में प्रस्तावित संशोधनों के प्रति आम सहमति व्यक्त की गयी थी बल्कि यह अनुरोध भी किया गया था कि इन संशोधनों को यथाशीघ्र संबंधित कानूनों में शामिल किया जाए ।

मुझे विश्वास है कि विद्युत नियम (संशोधन) विधेयक, 1991 को आम सहमति से और शीघ्र पारित किया जाएगा ताकि विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी के माध्यम से देश को अधिक से अधिक लाभ हो ।

महोदय, मैं उक्त विधेयक को विचारार्थ और पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत करता हूं ।

The question was proposed.

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): Sir, we can pass this Bill without any discusison.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I think, we can pass it without discussion.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU (Bihar): Sir, I want to make only one point.

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, I want to speak. . . (Interuptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If you want discusion, I have no objection because there is enough electricity here and and we are sitting in the light. Prof. M. G. K. Menon.

PROF. M. G. K. MENON (Rajasthere dealing with the Electricity Laws (Amendment) Bill, 1991. In the Statement of Objects and Reasons it is stated, and I read from para 2:

> "It is proposed to widen the scope of private sector participation in power generation, supply and distribution, by suitably amending the aforesaid Acts."

I am in agreement with the provisions which the hon. Minister has placed before us. However, I would like to bring many features both to the notice of the House as a whole and particularly of the Government in the matter of implementation.

We have to ask ourselves, what is the real rationale behind this amendment? Why do you need it? And it takes us to the basic situation we encountered in the country, namely, energy supply. I am deeply sorry that we have given many of these key elements in our development relatively low priority. We have to recognize that energy is the key factor in development. And if we look at India's energy situation today, essentially forty-four years after Independence, we find that the per capita energy consumption in this country is 250 kg. coal equivalent. Compared to twice that figure of developing countries as a whole, compared to ten times that figure of the developed world, of which North America is even twice as large as 11,000 kg. coal equivalent. That is where we are. On the energy availability per capita, we are at rock bottom. And we have to recognise that. And this, in my view, is the primary reflection of India's under-development. So I am fully with Government that you have to do something about it. Let me give you a dictum of one of our great scientists in the energy field, Dr. Homi Bhabha. What does he say?

> "No power is as expensive as having no power".

[Prof. M. G. K. Menon]

And we learn it to our cost when electricity just goes off and industry grinds to halt. It is true that we have come a long way since Independence. But we have not come a long enough. Nor have we come fast enough. We have moved certainly from a very small figure of something like 360 MW in 1947 to the current figure of around 65,000 MW. Yes, that is impressive. And we certainly did well in the Seventh Plan, and I think we ought to take credit for it. From a figure of around 42,000 MW at the end of the Sixth Plan, we targeted to have 22,245 MW. in the Seventh Plan and actually 21,400 MW were synchronized at the end of the Seventh Plan. It was almost hundred per cent accompalishment by Government largely due to the public sector production installation and commission. I think we must take note of it. However what is the picture beyond? India is a very large country with 843 million population according to the last census. Therefore, the Plan figure of the Energy Ministry was around 38,000 MW at a cost of Rs. 1,27,000 crores when it was projected. Why I mention these figures, is only to give the scale factor that we are talking of. We are not talking of a soap factory. We are not talking of trivial consumer goods. We are talking of one of the heaviest investments in prime sectors of the economy and the investments are of this magnitude. When finances of this magnitude were not found possible indeed one had to cut back from 38000 to something like 26000 MW. It should have been roughly the Seventh Plan figure itself. I would like the House to know, through you, that the prospects of the Eighth Plan and indeed of the Ninth Plan that would follow are not very good. They are indeed alarming. It is for this reason that the Government hoped that throuh these measures it will be able to somehow get more involvement through the private sector in the matter of energy generation.

[The Vice-Chairman (Dr. Nagen Saikia) in the Chair]

I would like to quote three sets of figures because energy is not electricity alone. I would really like t know from where this magnitude going to come. If you want powe generation, it will have to com through primary materials like co and oil. We will need in the-20 yea period between 1984-85 and 2004-0 an increase in coal production fror 140 million tonnes to 520 millio tonnes, in electricity gerneratio from 167 TWH to 818 TWH, in o production from 39 million tonnes t 118 million tonnes. I would just lik the House to recognise the magnitud of what we are talking about whe we talk of a great country like Indi and this has really to come from th people. Nobody can bail us out ex cept what is available as resource i our country.

Now, I would like to come to th most specific feature which is the Bil itself. As I said the rationale behin it is not just what is stated in the ob jects and reasons which are ver specific to this amendment. The ra tionale behind this is the magnitud of the problem that we face an therefore, the immediate urgency o ensuring that we have so much mor electricity generated in India, an bring everybody into the picture in cluding the private sector. Now when I have come to the Bill, ther are several comments I would like t make, if I may, with your permission Sir. First is, I do think that th statement relating to 20 years becom ing 30 years and 10 years becomin 20 years is almost immaterial an irrelevant because I don't think a the end of that period with the in vestments involved the Governmen will be in any position whatsoeve to acquire any of these assets. It i an almost meaningless exercise. Bu that can stand.

I would like to speak somehing or Clause 4 omitting sub-sections (4) (6) and (7) as on page 2 of the Bill Here I would like to say that it is stated that there will be a deletion o appointment of Government Director on the Board. I would like to draw the attention of the hon. Minister to

the fact that it may be worthwhile considering some enabling clause to appoint Government Directors on the Boards of private generating companies, mainly with a view to access to information in regard to operating agency and financial transactions. Such information is necessary to serve two purposes, as a means of comparison for SEB to emulate better operating indices and also as a means to ensure that the consumer is not burdened with unjustified expenditure and as a check to maximising profits. This is an essential service. So I would suggest that the hon. Minister considers this as a possibility.

I would now go on to another item which under section 29 of the principal Act, under 1(1). says: "Every scheme estimated to involve a capital expenditure exceeding...." I would like to substitute the words 'involve' to 'sum' by the words 'establish a generating capacity and involving foreign expenditure exceeding such capacity....' There is a very specific reason for this, and that is, as it stands, when we talk of these sums of money, which is Rs. 5 crore amount, that was in the old days in 1948 Act when this amount of Rs. 5 crores would probably instal 50-100 MW; but today it is nothing, and the private company on its own will do little. Its capital investment has a direct bearing on the profitability. Therefore, it is more important to consider also the foreign exchange component of such investment from the point of view of balance of payment position as well as in terms of indigenous production of our equipment.

I would like to go over to an aspect which the hon. Minister might take note of which is on page 3, line 40. This is under 11(2). I would like to include the words, before 'Plant Load Factor' 'Plant availability' because essentially one must remember that plant availability is a far more reliable efficiency norm. I leave it at that. I am sure this can be considered in greater detail.

I would like to question what is stated in the next page, page 4, at the top, the very first paragraph, where it says: "Provided that the terms, conditions and tariff for such sale..." which means, giving total freedom to the private sector companies to a operate on a commercial basis but akeep these State and Central sector SEBs under control. In my view, it is important that they are not also cash-starved. If subsidies are, indeed, given for them to give electricity on a subsidised basis, at a much lower cost to appropriate sectors, including the rural sector, let that be transferred to them; let that be given directly to the SEBs, the public sector units, and they must also be allowed to operate on commercial terms. I see no rationale behind the fact that this clause will apply to private sector but will not apply to the large public sector which is operating in the country today. Under the proposed new Section 55(1), there is a statement about reasonable directions, as the Board may give, concerning maximum economy and efficiency. I find it somewhat facetious. The way most of our electricity operations have been carried on up till now in terms of the PLF, in terms of the plant availability and in terms of the transmission losses, I would say that "Doctor heal thyself". Don't give advice to people until you have managed to do it properly by yourselves. There is also the question relating to the proposed Section 55 (3) which refers to the integrated grid operation. We have to ask ourselves as to why these integrated grid operations are not working smoothly. It is rather technical in a sense because, first of all, there are technical reasons like absence of tie-lines, insufficient transfer capacity, inadequate reactive compensation and so on. But the commercial reasons are equally important. To maximise profit and efficiency, the private operators, and for that matter, the Government, would like to operate it at the highest PLF provided the plant availability is related to good maintenance and

[Prof. M. G. K. Menon]

minimal breakdowns. However, in most regions, other than the Western, the off-peak loads do not match that many stations have to back down. No one is prepared to do so voluntarily, as the public sector units are afraid to show lower PLF. One can go in detail. Today, the Regional Boards and other Regional Load Despatch Centres have no statutory authority to do so. I would like to suggest two things for the considerations of the hon. Minister. One is, to give statutory powers to the Regional Boards, and the other is to lay down the principle of ranking on the basis of per-unit cost. Now, there are further features in detail which relate to clause 14, at the bottom of page 4. Now, most of this has been proposed as a formula so that it will become attractive to the private sector to be able to participate in power generation. I would like to bring to your notice certain basic features. At the present moment, if you look at the study which was done a few years ago by the Associated Chambers of Commerce, the average normative cost of power generation was 95 p. per unit, while the effective average realisation, except for one or two SEBs was far below, almost half. This could be easily Rs. 1.30 or more. So, new units in the power sector—with the inflation and escalation that are taking place—will not be able to sell power at less than Rs. 1.05. Since SEBs have the distribution responsibility, including that to the large subsidised rural sector, only those with proportionally higher industrial load —for example, the States like Maharashtra, Karnataka and so on—will be able to buy at this rate. So, the question will be how much investment will take place outside these States where the demand for power far exceeds the supply. And we should not have a situation where, in those States and in the rural sector, the responsibility becomes that of the SEBs alone.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Kindly be brief and conclude.

PROF. M. G. K. MENON: Now, I shall only pose several questions to the hon. Minister. The operative issues have been left in the agreement for promulgation by the Government. I would like to have information on the rate of return, the rate of depreciation and the norms of efficiency. I would also like to find out as to what is going to happen with regard to the National Power Transmission Corporation. It is also important to comment on another thing. You talk of electricity generation. Upstream, you have materials like coal and gas that I mentioned, and downstream, the transmission. Coal, today, is entirely in the public sector. The transportation system—largely, the Railways—is also in the public sector. The quality of coal, in terms of ash, stone and other impurities, becomes important. Transmission downstream,—taking it into not only high-tension lines, but low-tension lines as well, and the widely-distributed rural electrification and other systems— today, involves a loss of as much as 18—20 per cent, largely in the low-tension area.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Prof. Menon, kindly put your questions and conclude.

PROF. M. G. K. MENON: A very basic point I would like to make is, we are only considering rather a small facet of the total energy scenario. We should not expect that, just by this, we are going to get a very large investment, a very large private sector involvement, which will transform the energy scenario in this country. It is tied up with much else and, therefore, all of them have to be suitably dealt with. The magnitude of the investment, the speed and scale involved, really calls for a well-planned and co-ordinated approach with all these linkages suitably done. I hope the Minister of Energy is aware of it. I hope he will see to it and plan it accordingly.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Naresh Puglia. You shall have to be very brief.

श्री नरेश पुगलिया (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे ऊर्जा मंत्री जी इलेक्ट्रिसिटी ला अमेंडमेंट बिल, 1991 लाये है । अभी तक देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता था और खासकर के 70.5 प्रतिशत स्टेट सेक्टर में, 25.3 प्रतिशत सेंटर सेक्टर में और 4.3 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में जो होता था । लेकिन इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य आज देश में पावर की कमी है । प्रति मेगावाट पावर बनाने के लिये अगर थर्मल पावर स्टेशन लगता है तो उस पर 2.25 करोड़ प्रति मेगावाट लगते हैं और इस कारण केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इतने बड़े पैमाने पर उसे नहीं लगा सकती हैं । आप देख रहे हैं कि देश की औद्योगिक नीति को हमारी सरकार ने बदला है और उसका असर केंद्र और राज्यों की जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है उन पर भी हो रहा है । महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं महाराष्ट्र के वह देश को बिजली भी देता है और कोयला भी देता है । खासकर जिस राज्य से मैं आता हूं वह राज्य बिजली के उत्पादन में स्वयं पूर्ण है। इस मामले में वह स्वयं पूर्ण ही नहीं बल्कि आज बाजू के राज्यों को भी मुसीबत में बिजली सप्लाई करता है । लेकिन इस अमेंडमेंट को लाने के बाद मंत्री महोदय से हम कहना चाहेंगे कि कहीं ऐसा न हो केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से जो हमारे बड़े बड़े बिजली घर बने हैं उन पर किसी प्रकार का आघात हो । महाराष्ट्र के अंदर एक साल पहले उस समय की राज्य सरकार ने पब्लिक सेक्टर में और खास करके स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर प्लांट था उसका एक्सपेंशन प्राइवेट सेक्टर में देने की कोशिश की थी और केंद्र सरकार से इसकी परमीशन मांगी थी । उस समय हमने इसका विरोध किया था और इस हाउस में हमने रिकार्ड कराया था कि केंद्र या राज्य सरकार एक्जिस्टिंग पावर प्लांट जो हैं चाहे वे हाइड्रो प्रोजक्ट हो और चाहे वे थर्मल प्रोजक्ट हो, उसका एक्सपेंशन अगर करना है तो उसको पब्लिक सेक्टर में किया जाय न कि प्राइवेट सेक्टर में : क्योंकि आपने जब एक बार यह पावर प्लांट लगाया है तो उसके लिये किसानों ने जो जमीन दी, आपने उसका मुआवजा दिया, पानी के लिये डेम बनाया, रिहैबिलिटेशन के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया और यह सब करने के बाद अगर एक्सपेंशन में प्राइवेट सेक्टर को घुसाते हो तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में क्लेश आयेगा । इस कारण हमने ऊर्जा मंत्री जी से विनती की थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस तरह की परामीशन न दे । लेकिन इस बिल के बाद अगर केंद्रीय सरकार ने यह बिल पास करने के बाद राज्यों को ऐसी परमीशन दी, प्राइवेट सेक्टर की, तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आज तक आपके पास ऐसे कितने प्रपोजल आये हैं ? एन०टी०पी०सी० जो हमारा सेंटर का कारपोरेशन है, इसने पिछले 10 सालों में देश को बहुत अच्छी सेवा की है तथा सेंटर का जो हाइड्रो कारपोरेशन है, उसने भी बहुत अच्छी सेवा की है । उसके माध्यम से बिजली उत्पादन में 85 प्रतिशत प्रोडक्शन एचीवमेंट हुआ है । अगर आप राज्यों के बिजली बोर्ड देखेंगे जिसमें 50-55 प्रतिशत भी बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता, आज उसी का नतीजा यह हो रहा है कि 1800 करोड़ रुपया कोल इण्डिया को सब बिजली बोर्डों ने देना बाकी है और तीन हजार करोड़ रुपये बिजली बोर्डों को पब्लिक से लेना है । इसका कारण यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको शुरु से सीरियसली नहीं लिया और अच्छे ढंग से मोनिटर नहीं किया और स्टेटस को छूट दे दी जिसमें राजकीय हस्तक्षेप हुआ, भ्रष्टाचार हुआ । इस सारी स्थिति का परिणाम यह हो रहा है कि ऐसे क्षेत्र को हमें आज प्राइवेट सेक्टर में पूंजीपतियों के हाथ में देना पड़ रहा है । हम उम्मीद करेंगे कि केन्द्र सरकार ने जितने प्रोजेक्ट्स का अब तक सर्वे कराया है उदाहरण के तौर पर चन्द्रपुर का सुपर थर्मल पावर स्टेशन एन०टी०पी०सी० के माध्यम से हम पिछले पांच साल से कोशिश कर रहे हैं, तीन चार मंत्री भी बदल चुके है कोल मिनिस्ट्री के हां कहने के बावजूद उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला और उसे आज भी आठवीं योजना में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[श्री नरेश पुगलिया]

यह दो हजार मैगावाट का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है । इसके लिए सदन के नेता माननीय चव्हाण साहब ने आपकी मिनिस्ट्री और कोल मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है । मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश में एन०टी०पी०सी , स्टेट गवर्नमेंट के जिन हाईड्रो प्रोजेक्ट्स का सर्वे हो चुका है और साइट सेलेक्शन भी हो चुका है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप मेहरबानी कर के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक अंडर-टेकिंग्स से निकाल कर प्राइवेट लोगों के हाथ में न दें । वे नये प्रोजेक्ट लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करें । साथ ही साथ थर्मल प्रोजेक्ट देते समय उनको समय पर कोयला न मिलने से कई प्रोजेक्ट सफर कर रहे हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोयले की व्यवस्था का काम भी आप उन्हीं को सौंप दें । अपनी माइन्स से निकाल कर कोयला खुद सप्लाई करें तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी । मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आठवीं योजना में जो 38,369 मैगावाट की जो योजना, बनाई है, इसमें से आप कितने प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में देने वाले हैं और कितने प्रोजेक्ट आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से करने वाले हैं ? इसमें जो आपकी 1,28,000 करोड़ रुपये की लागत लगने वाली है इसके लिए आप को कितना पैसा आठवीं पंचवर्षीय योजना में मिलने वाला है, इसकी भी जानकारी मंत्री महोदय हमें दें । मैं खास तौर पर यह जानना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में आप जो प्रोजेक्ट्स देने जा रहे हैं इसमें कौन कौन सी सुविधा देंगे और इस प्रकार से इस सेक्टर में यह जो प्राइवेट सेक्टर को लाने का आप बिल लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । धन्यवाद ।

SHRI E. BALANANDAN: Sir, I rise to oppose this Bill. We are dealing with a subject which has basic bearing on our development. As hon. Mr. M. G. K. Menon said, "What have we achieved?" In India for the last so many years we have been generating power. We started with 1300 mw. Now we are having 65,000 mw. Out of the 5 lakh villages we have given electricity to more than 4.50 lakh villages in India. And, Sir, how do we distribute electricity? In Andhra Pradesh, I know, in the rural sector up to 5 HP motors running for irrigation it is given free. Many kinds of tariff rates are there in each State. I can site one latest example. In the budget of Kerala it is stated that up to 20 units they will not charge money, it will be free. This type of concessions are being given to the agricultural and small-scale industrial sector and those industries are power intensive industries.

This kind of different tariff tariff systems are being followed. What is the totality of the effect? We say that we are self-sufficient in food production. What is the basic contribution for that? We have supplied electric energy to the agricultrists at moderate rates and, in certain cases, we have given it free. How was it possible? It was possible because electricity generation, generally, is kept under the public sector. This should not be forgotten. We are boasting of the country's progress. How have we achieved it? It is achieved on the basis of development of the public sector infrastructure, basically of energy, that too, electricity. And one fine evening you are coming with a Bill with some clauses, saying that you want to invite the private sector. I have no objection to the private sector. They are doing business in the country. But why are you inviting them? What do you want?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): We want more power production.

SHRI E. BALANANDAN: You can speak when your chance comes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please don't interrupt. (*Interruptions*). Mr. Narayanasamy, if you interrupt you will lose your chance.

SHRI E. BALANANDAN: Sir, we know the problem that the Government of India is facing. For the Eighth Plan, the original suggestion by the CEA was 48,000 megawatt. Our Plan started with 38,000 megawatt and then the Planning Commission reduced it to 25,000 megawatt—and for that also we have no money. That is the situation today. The Government says, we have no resources and therefore we are trying to find some resources from the private sector and for that we are giving them a lot of concessions. But the Power Minister is not considering whether any kind of concessions can be given to the public sector.. (*Time bell*).. Sir. will take two minutes more because this is a basic subject we are dealing with at the dead of night. This had to be discussed earlier, but leave it.

Now the question is, how do we manage this thing? There are two systems which are going to work simultaneously. Under one system, according to your amendment under clause 43A, the Government of India is going to keep the power to notify the tariff, whenever they want to decide, on the basis of reasonable returns, Reserve Bank rates, etc., etc., and the Government of India will decide it by notification. This is what is given here. In the next page it is stated that the public sector companies the Electricity Boards — have no rights; they are not given any rights. So the question is this: From the private sector you are ensuring profit and in the public sector you are limiting it only to three per cent. That was the right given earlier. The State Governments and the Central Government have to give them the direction to work within such a framework so as to ensure total development of the country. Therefore, the agriculture sector, the small-scale sector and all such sectors have to be given special concessions by the electricity generating sector, that is, the Electricity Boards or any other corporations under the Government sector.

Now, I don't think the private sector has a lot of money in hand. Even if the money is there, how will you mobilize it? I will give you the example of Karnataka. One Government company is there. That company is producing electricity and is making profit. How does it do it? They got the money from the public when they floated the company, not in the private sector but in the Government sector. The public money, they got money, they got the money, they got the money, they started the industry and they are running it. Why do you go to the private sector alone? The public sector has its own standing.

Another aspect I want to bring to your notice. Sir, only one or two minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The extra time that was fixed by you yourself, is over.

SHRI E. BALANANDAN: My point is that this Bill is here. We are coming to something.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGGEN SAIKIA): Please conclude.

SHRI E. BALANANDAN: While you are in the Chair, Sir, you should protect the rights of the Members. I am only saying that this question we are discussing is very serious. For electricity generation we have developed another infrastructure. That is, we are able to produce electricity generators and other required equipment in our industries. We have built the infrastructure for that. This is a major achievement. If you are going to give it to the private sector, then, our BHEL will be idle. We are worried about the foreign exchange factor. We are not having money. Our

[Shri E. B. Balanandan]

own industrial infrastructure developed for producing electricity generators in our country, will go idle because of this kind of a step, immediately inviting the private sector without any control over it whatsoever, and you are keeping every control over the public sector alone.

Sir, you are not allowing me more time.

I want to suggest two, three things. The public setcor can start independent companies which can run efficiently. The Minister was talking about the efficient functioning of our NTPC, isn't it? How is it? Is it in the private sector or in the public sector? You are saying that the public sector is all bad. The NTPC has proved that this is incorrect. It can be run profitably and efficiently. Therefore, it can be run efficiently too. Therefore, I am saying that companies can be established under the public sector to see that their financial difficulties are got over. (Interruptions) Wait, wait.

Therefore, the private sector is not going to be moved.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now please conclude.

SHRI E. BALANANDAN: I am only saying that there are a lot of deficiencies there in the Electricity Boards in the public sector. I know that many of them are the creation of the Government. In one State, I know, 5,000 workers were appointed in the Electricity Board. The workers came to work. There was no chair because the Minister decided that. So many things of this kind are there. I have no time to tell them. If you want to increase the efficiency of the Electricity Boards and the public sector operations, you should bring in the workers. The Electricity Supply Act should be further amended. Why? For giving 50 per cent representation for the workers, engineers and workers, who are manning the industry. With this opening of the private sector of a special category, giving freedom to them to take enough of profits they will be only motivated in profits and not in the development of the country. We want to develop our country.

I would like to give you the example of China. There the electricty production is just the double of ours. Therefore Sir, I oppose this Bill. I want that this question should be taken very seriously by the Government. I don't want in any way to invite the private sector in this. I oppose this Bill.

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, I recall an evening like this in the 1980 election — campaign in my former constituency in a rural area, the farmers told me one thing, "We have a very good crop. The crop is standing there. We have water in the well. But because there is no power, we cannot supply water to this crop, and this crop might die. We are getting tears of blood in our eyes. This was in 1980. Eleven years have passed. I don't think that anyone can say with great confidence that the situation has improved to a considerable extent. I doubt whether it has improved at all. This is an all-India experience.

I think that this Bill is long overdue. I recall that when Mrs. Gandhi was the Prime Minister in 1980s, she had thought of this option and the Ministers expressed in public meetings the opinion about encouraging the private sector to come up and set up power projects. Mr. Rajiv Gandhi and his Government did the same. There was a Bill, prepared. There was a discussion held with entrepreneurs. But somehow or other it did not fructify. I think the successor Government of Mr. V. P. Singh had the same idea. I want to congratulate the present Government and the Minister for Energy for bringing this very long overdue Bill to become an Act. It is not for the sake of private sector or public sector. It is for pro-

10.00 P.M. viding electricity to the nation as such. I will come to that because this is not privatisation. The participation of private sector and additonality will be there. We have got lots of statistics. We have problems of large gaps in supply and demand. Actually there is a negative

gap of 17 per cent today. I agree with my very learned and highly vocal friend Vishvjit P. Singh, about not depending upon statistics; that even though these figures may be there on paper, in reality when you visit different villages in different parts of the country you find on paper electrification is complete, but in reality power is not available there. Now, throughout these years we have seen the quality of supply of power. In this Parliament House we suffer from power cuts and sudden blackouts. There have been power cuts in every State. I do not think there is a single State which does not have power cut. That cannot lead to growth. There are sudden stoppages. Different areas in the city of Calcutta have no power supply for four hours out of 24 hours. All data are available. The worst is the voltage fluctuation which affects everything from home equipment to various other equipment from a farmer's motor pump to any activity whether is in the public sector or in the private sector. Who suffers because of this? I think every sector of the economy and the nation as a whole suffers. If we look at the economy of every State, I think every State is in a great deficit today. We read in newspapers whether it is West Bengal or Bihar or any other State that there is no money. Some States have problems of making payments towards the salaries of their employees. One of the fatcors is the budgetary support to various public sector organistaions. I will not name, but even the Leftist States find it extremely difficult how to extend such budgetary support year after year. The major amount from that is taken away by the State Electricity Boards. Mr. Balanandan has mentioned about the political pressures for employing 5,000 people or whatever their number, but the result is that the State Electricity Boards — I think in every State it is so — are unable to pay to Coal India Ltd. So, they cannot get coal. They have their own deficits. They have to make it through their Budgetary sources, but they cannot make it. Hence they cannot put up additional electricity supply system in their own States. You will be surprised that till 31st March, 1990, end of the Seventh Plan period, the total loss of SEBs was Rs. 12,040 crores. If you add loss of last year, 1991 it is Rs. 4036 crores in one year, If you project it to five years. it may be over Rs. 24000 crores.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude.

SHRI VIREN J. SHAH: The first speaker, Prof. M.G.K. Menon, spoke exactly for 26 minutes and I have not yet begun.

So, Rs. 16.00 crore loss is already there. It is equal to the Defence Budget. You keep that in mind. Moreover, electricity affects generation of wealth whether it is in the agricultural sector or in the industrial sector. Just for comparison NTPC is certainly a very good example of efficiency. There are States which are not taking power from it even though they may be short of electricity But if you take the Tata Power Company or the Rihand Power projec their efficiency is supposed to be over 100 per cent. So, in case a new economic direction has to be given, we need more electricity. There cannot be two opinions on this. Moreover, another important objective of removing poverty in rural areas cannot be done unless we provide electricity in those rural sectors making it possible for them to generate wealth in whatever way. I do not know whether most of us know that our cost of power is amongst the highest in the world. I was in Turkey two years back when they made comparison of twenty countries, when Turkey's power cost was the highest. India was not included in those 20 countries. At that time our power cost position in Maharashtra was twice as high. We have to keep this in mind. I am not going into the Eighth Plan target. That is going to be very much reduced. But at the end of the Eighth Plan we might have a gap of —20 percent. We have World Bank loan unutilised running up to Rs. 15000 crores in terms of

[Shri VIREN J. SHAH]

dollars $6 billion up to the end of 1990. We must see that it is utilised because rupee counterpart is unavailable. We must ensure that projects do not suffer because of that.

Now two more points I want to mention. The Minister of Energy is also having experience about it. One of the major problems is the problem posed by the Ministry of Environment in clearing the projects in respect of public sector. The environment has to be guarded. We must find a solution by which the Ministry of Environment does not sit on the heads of the basic power projects or the proposed projects in the private sector.

While supporting this Bill, I would like to point out that in the Bill there is a provision that every scheme has to get the Central Government concurrence. My only request is that we must find out a mechanism by which there is no undue delay in giving concurrence to the projects. It must be processed speedily. I was told right now there are 17 permission required for clearance. Cut it down to one and do that soon.

Then about the gas usage, there is a wastage. I have got with me CAG report on the HBJ pipeline where Rs. 1700 crores have been spent but the gas has not yet been utilised. The flaring of gas in Bombay High is taking place. The Government of Maharashtra has requested a number of times that they will utilise it to generate electric power. A proper case has been made out. But your Ministry, Mr. Minister, is sitting on it and not giving any sanction. I request you to take immediate steps to clear it.

My last two points are: Move fast now. I would not say get off your butt but do it without my saying so. In future also you have to consider use of cooperative sector particularly for rural electrification. I was told that in the United States there are 1000 cooperative societies generating power in rural areas and they are very successful. May be some day you may think of it. Secondly to consider build, operate and transfer inviting even foreign cooperatives to build it, operate it and transfer it as has been done by Turkey and others. Once in 1977, Mr. George Ferdandes had proposed a similar suggestion for foreign investment which can enable the country to generate power so that we may not face the problem to resource crunch. I and my party support this Bill. I wish you to succeed in implementing this Bill, but implement it fast enough and properly.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Shri Anant Ram Jaiswal. You shall have to be very brief. You have only four minutes.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, एक मैं शुरू में ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर विचार करने के लिए हम रात में बैठ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए इस तरह की पाबंदी आप मत लगाइए कि कोई बोल ही न पाए । मान्यवर, चार मिनट में कुछ कहा नहीं जा सकता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You try to conclude.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: I will try. But it is not possible to conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You know the strength of your party and the time allotted to your party. I cannot help you. Please make your points and conclude.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: I will not be able to conclude within that time.

श्री रजनी रंजन साहू : सपोर्ट कर दीजिए या अपोज कर दीजिए ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : सपोर्ट तो करना ही है ।

मान्यवर, इस शताब्दी के मध्य में उत्साह था और वह जुनून की हद तक था कि प्राइवेट सेक्टर और निजी सेक्टर के स्थान पर पब्लिक सेक्टर को लाया जाए

और उसी वक्त जो बिजली उत्पादन और आपूर्ति के कारखाने थे, वह भी सार्वजनिक क्षेत्र में लाए जा रहे थे । तो उस वक्त खुशी हुई थी कि पब्लिक सेक्टर जो नफा ज्यादा लेता है वह हट जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र में यह आएगा तो मुनाफे की वृत्ति कम होगी, बिजली सस्ती दर पर मिलेगी । शुरु में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जब हम इस सदी के आखिरी दशक में हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि विकास अवरूद्ध हो गया है, बिजली का उत्पादन ठप्प हो गया है और यहां तक जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे, वे सब कर्जे में डूबे हुए हैं । और जो हमारी जानकारी है, उसके हिसाब से साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए उनके ऊपर कर्जा है । तो ऐसी हालत में न तो बिजली जनरेशन का काम कर सकते हैं और न आपूर्ति का ही काम ठीक कर सकते हैं । तो यह बिल्कुल ठप्प हो गया है और जहां तक बिजली का सवाल है, इसमें बार-बार दोहराने की जरुरत नहीं है कि यह ऐसी आवश्यकता है कि जिसके बगैर कारखाना नहीं चल सकता, न खेत का काम हो सकता है और न घरेलू काम हो सकता है, तो इसकी आपूर्ति की इतनी जरूरत है और सरकार जिस आर्थिक संकट से गुजर रही है, उसमें उनके पास कुछ है भी नहीं कि वह स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस की कुछ मदद कर सके । तो ऐसी हालत में इस सरकार को यह बिल आज इस सदन में विचार के लिए लाना पड़ा । जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से यह इस सरकार की सोच नहीं है, इसके पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, उसके पहले राजीव गांधी की सरकार और फिर बाद में चन्द्रशेखर की सरकार, सबने इस पर विचार किया और सब इस राय के थे कि इस बिल को लाया जाए । यह पहले नहीं लाया जा सका और आज कल्पनाथ राय जी के माध्यम से, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उनके माध्यम से आज यह बिल आया है । इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं । यह बिल आज की मांग है, जनता की आवाज है, इसलिए हम उनको बधाई दे रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे यहां इस सदन में विज्ञान की जानी-मानी हस्ती हैं—प्रो० मेनन, उनकी विज्ञान और ऐसे विषयों की जानकारी और समझ हम लोगों से ज्यादा है, तो उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनको तो वे ध्यान में रखें ही और उन पर अमल भी करें, लेकिन उसके साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि आम तौर पर यह डर है कि अगर यह मामला निजी हाथ में चला जाएगा तो उससे बिजली के रेट बहुत बढ़ जाएंगे और दूसरी चीज यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में इसके रहते हुए खेती वगैरह को जो हम रियायत देते हैं, वह आगे नहीं मिल पाएगी । तो एक जवाब तो मैं भी उसका दे सकता हूं, उसकी मिसाल है महाराष्ट्र । महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र साथ-साथ चल रहे हैं और वहां पर देखने में आ रहा है कि बिजली के मामले में भी वे पूरी तरह से सेल्फ सफिशेंट हैं और जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि आजू-बाजू के इलाकों में भी वे बिजली दे रहे हैं । इसी के साथ-साथ वहां पर देखने में यह भी आता है कम्पेरिजन में कि थोड़ा निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से आगे ही है और अच्छी सेवा दे रहा है । जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, वाम मोर्चा सरकार ने भी सस्तुति की है सरकार से कि आर०पी० गोयनका को बिजली का कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी जाए और मुझे यह पता चला है कि वह इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बंगाल का है, उसके संचालन में उनका हाथ भी है और नया कारखाना वे लगा सकें, इसके लिए उन्होंने संस्तुति की है लेफ्ट फ्रंट सरकार ने । तो मेरा यह अनुरोध है कि चूंकि संसाधन की कमी है, बिजली की आवश्यकता है, खाली निजी क्षेत्र में बिजली खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, जैसा मेनन जी ने कहा कि ऊर्जा के और भी क्षेत्र हैं, स्रोत हैं और उनको भी केप करना बहुत आवश्यक है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि उनकी तरफ भी ध्यान दें और खाली यह बिल लाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उस पर तेजी से अमल किया जाए तभी कुछ नतीजा निकल पाएगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं और बिल का समर्थन करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Dr. Y. Sivaji. The time allotted is four minutes.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, I am glad that the Government has come out with the proposal for privatisation of power generation. (*Interruptions*).

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): No. It is not so.

SHRI KALP NATH RAI: Let him speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): It is his opinion. Let him say what he likes to.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: And it appears that it is a clearcut deviation from the cherished goal of Jawaharlal, Madam Gandhi and Rajiv Gandhi. It appears that they are learning lessons from USSR. It is a fact that the Electricity Boards throughout the country are in debt and they are known for their inefficiency. Several projects proposed by various State Governments are pending clearance with the Central Government, the Planning Commission and at other places. Added to that, the Central Government is creating some quarrel or the other among various State Governments for nationalisation of power plants as well as irrigation projects. Sir, it is a fact that the State Electricity Boards are not serious to collect the dues from the industrialists. There is a collusion between the Electricity Boards and the industries. To my knowledge, the Andhra Pradesh State Electricity Board is to collect more than Rs. 350 crores from the industrialists and from thirty industries, the overdues are more than Rs. 250 crores. The Standing Counsels of the Electricity Boards are in collusion with the industrialists and they are successful in their efforts to get it delayed in the legal battle, both at the Supreme Court as well as the High Court level. Sir, the power supply to agriculture is erratic and the Government is not serious to supply power at least for eight to nine hours during day-time and thereby the agricultural operations are being affected to a large extent. The working group of Planning Commission recommended that an outlay of Rs. 1,28,000 crores is needed for the Eighth Plan for power generation and having found that it is not possible to allocate such a large amount, the Union Government found it convenient to open the doors for the private sector's participation in power generation as well as supply and distribution. I would like to know whether the Government propose either to provide power generation or captive power generation. I feel that the problems will remain the same unless the attitude of the Government changes at the bureaucratic level to clear the projects at an earlier date.

(*Interruptions*)

[The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar) in the Chair]

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, please give me one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Narayanasamy, what is it about? Your name is not there.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, that is why I sought your permission. The Chief Minister of Pondicherry has made a request for allocating 50 megawatts of power from the Central Grid. The reason giving rise to this request is that small scale industries are developing in my State and we are having only 130 megawatts of power. We do not have power generating units. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can take it up with the Minister.

SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to know from the Minister whether he is acceding to our demand.

श्री रजनी रंजन साहू : : महोदय, एक प्वाईंट मेरा आप सुन लीजिए । मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि बिहार की हालत बहुत बदतर है । बिजली का उत्पादन वहां नहीं है । पिछले दिनों में जो भी उपेक्षा की गई है, उन बातों को भूलकर मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा और मैं मांग करता हूं कि नार्दन ग्रिड से ईस्टर्न जोन को जोड़ा जाए और रिहंद से बिहार शरीफ तक बैक टू बैक सिस्टम चालू किया जाए । मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन सदन के पटल पर चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो निजी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन होने वाला है, उसमें बिहार को उसका कितना हिस्सा मिलेगा ?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा में हमारे कई मित्रों ने भाग लिया है उनमें एम०जी०के० मेनन और अन्य साथी शामिल हैं । मैं कहना चाहता हूं कि दुनियां में जो परिवर्तन का झंझावत चल रहा है, उस परिवर्तन में हिंदुस्तान को भी अपनी दिशा निर्धारित करनी होगी और यह जो विधेयक लाया गया है... **(व्यवधान)**

SHRI JAGESH DESAI: Are you doing it because you have no resources or because the world changes?

SHRI V. NARAYANASAMY: There is demand also.

SHRI KALP NATH RAI: Why do you interrupt like this? हमारे प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी की सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति लाई है, उस नीति को हम कैसे सफल, करेंगे, कैसे खेती सुधारेंगे, कैसे कारखाने सुधारेंगे कैसे तकनीक क्रांति होगी, कैसे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, इन सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए यह विधेयक लाया गया है । मेरे कई मित्रों ने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है । Public sector will occupy the commanding heights of the economy. यह हमारी नीति है लेकिन एडीशनैलटी ऑफ रिसोर्सेज, साधनों को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का भी दरवाजा हमने खोला है कि वे लोग भी इस क्षेत्र में आएं और बिजली का उत्पादन करें ताक हम देश की समस्याओं को हल कर सकें । एम० जी०के० मेनन साहब बहुत विद्वान हैं और उन्होंने इस विधेयक के संबंध में कई बातें कहीं । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जैसा विकासशील देश जब आजाद हुआ तो भूखा, नंगा, कंगाल हिंदुस्तान था और उसके बाद कृषि के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में जितना विकास हिंदुस्तान ने किया है उतना दुनियां के किसी विकासशील देश ने नहीं किया है । 5 करोड़ टन से 18 करोड़ टन गल्ले का उत्पादन हुआ है और 1360 मैगावाट बिजली का उत्पादन जो पहले होता था, आज 66,000 मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है ।

दूसरा, पंचवर्षीय योजना की बात की गई । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में लगातार बिजली का उत्पादन बढ़ा लेकिन एक सरकार 1977 में आई थी । उस जमाने में कोई योजना ही नहीं बनी । छठी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ, उसमें कोई बिजली का टारगेट तय ही हुआ, कोई उत्पादन नहीं हुआ और कोई प्रोजेक्ट नहीं बना । फिर इसके बाद हिंदुस्तान में 1989 में एक सरकार आई । 1985 में राजीव गांधी के नेतत्व में सरकार बनी और उसने फैसला किया कि 22,245 मैगावाट सातवीं पंचवर्षीयर योजना का लक्ष्य होगा । पूर आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में 22,245 मैगावाट के पूर्ण लक्ष्य को राजीव गांधी की सरकार ने एचीव किया । फिर 1989 में एक सरकार आ गई । वह सरकार न तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसविदा बना पाई और न ही आठवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण तैयार कर पाई । कितना हमारा टारगेट होगा, वह तय नहीं कर पाई और अब नरसिंह राव जी की सरकार 1 अप्रैल, 1992 को आठवीं पंचवर्षीय योजना को लाग करने जा रही है और उसमें हमने अपना लक्ष्य 38,000

[Shri Kalpnath Rai]

मैगावाट रखा है और हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करने जा रहे हैं । लेकिन जो 2 वर्षों में सत्यानाश आ उसका फल कौन भोगेगा ?

आप हमारे मित्र हैं, विरोधी दल के है । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय बात हो रही है । अभी हमारे मित्र बालानंदन जी ने कहा कि प्राइवेट सैक्टर, अरे

we are not going to privatise the public sector. Private sector and public sector are supplementary and complementary to each other.

मैंबालानंदन जी आपसे कहना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद प्रसव वेदना से गुजर रहा है । इतिहास चक्र को देखिए, चक्र कैसे चल रहा है पूरे साम्यवाद का जनतंत्रीकरण हो रहा है : चैकोस्लोवाकिया, यगोस्लाविया, रुस से उखाड़कर फैंक दिया गया है । साम्यवाद कहां है ? दूसरी बात यह है कि सदन में आप कुछ बात करेंगे लेकिन इनकी सी०पी०एम० की सरकार, केरल से ये आते हैं, इनकी केरल की सी०पी०एम० सरकार ने बनिहाल हाइडल प्रोजेक्ट को प्राइवेट सेक्टर में लगाने के लिए पत्र लिखा है । इसी तरह से सी० पी०एम० के हमारे मित्र श्री ज्योति बसु जी भी प्राइवेट सेक्टर में वजाज का कारखाना लगाने के लिए आर०पी० गोयेंका के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं । अभी एक दूसरा प्राइवेट सेक्टर का कारखाना लगाने के लिए रतन टाटा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के पास भेजा है । आपकी केरल की सरकार प्राइवेट सेक्टर चाहती है, लेकिन आप यहां पर वकील बन गए, यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन दुनिया में जितने भी पशु या पक्षी होते हैं सब को दिन में दिखाई देता है, मैंगर एक ऐसा भी जानवर है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता । मैं कहना चाहता हूं कि--

—Now there will be a generating company who will transmit power from one place to another place. That work will be done by the National Power Corporation.

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने एक बात बताई । केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रीय परियोजनाओं को प्राइवेट सेक्टर को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । आदरणीय पुगलिया जी ने कहा कि हमारा 32269 मैगावाट का लक्ष्य है जिसे हम पूरा करेंगे ? लेकिन हमारी इतनी अवश्य मांग है कि हिन्दुस्तान की गली गली में, गांव गांव में बिजली पहुंचाने के लिए यदि हमें 38269 मैगावाट के लक्ष्य को पूरा भी कर ले तो भी हम बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकेंगे । हमने 8वो पंचवर्षीय योजना में 62 हजार मैगावाट का लक्ष्य रखा है । वह पब्लिक सेक्टर का लक्ष्य है । प्राइवेट सेक्टर को भी हमने कहा है कि आइए आप भी प्रोजेक्ट खोलिए । कंट्रोल हमारा होगा, हमारे ग्रिड में पावर आएगी ।

अभी हमारे माननीय सदस्य प्रो० एम०जी०के० मेनन साहब ने एक बात कही कि आप बताइए कि पहले प्रदेश सरकार 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को तय करती थी, इससे उपर जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको तय करना पड़ता था । तो अब रुपए का अवमूल्यन हो गया है । इसलिए जो स्थिति होगी उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार नोटिफिकेशन करके कानून के अंतर्गत प्रावधान करेगी ।

श्री जगेश देसाई : टैरिफ कौन तय करेगा ?

श्री कल्पनाथ राय : टैरिफ का सिद्धान्त और नेशनल ट्रांसमिशन कारपोरेशन का सवाल उन्होंने उठाया । नेशनल ट्रांसमिशन कारपोरेशन बनाने की योजना राजीव गांधी जी ने तैयार की थी । इसके लिए हिन्दुस्तान को हमने 5 जोन्स में बांटा है--साउथ, नार्थ, ईस्ट, वैस्ट और नार्थ-ईस्ट और हमने एक एरिया की सरप्लस पावर को दूसरे डेफिसिट एरिया में ले जाने के लिए ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम वैस्टर्न को, नादर्न को पावर दे सकेंगे जैसे हमने रिहन्द से दिल्ली को पावर सप्लाई करने के लिए 900 किलोमीटर की लंबी

ट्रांसमिशन लाइन तैयार की है जो एशिया की सबसे बड़ी लाइन है और जिससे 1500 मैगावाट बिजली सप्लाई की जा सकेगी । उस योजना को चालू किया जाएगा । हम नादर्न से ईस्टर्न को जोड़ने जा रहे हैं, हम सदर्न से ईस्टर्न को जोड़ने जा रहे हैं । पूरी कंटरी को ईस्टर्न-वेस्टर्न रीजन से जोड़ेंगे और फिर नेशनल ग्रिड का जो कांसेप्ट होगा उसको हम लागू करेंगे ।

श्री रजनी रंजन साहू : बिहार के बारे में बता दीजिए ।

श्री जगेश देसाई : प्राइवेट सेक्टर के जनरेशन को... (व्यवधान)

श्री कमलनाथ राय : अगर कोई प्राइवेट पूंजीपति कोई कारखाना खोलता है और उससे 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है और उसको केवल अपने कारखाने के लिए 100 मेगावाट बिजली चाहिए तो 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली जो है यदि वह बेचना चाहेगा तो हम उसको खरीद लेंगे । उस बिजली को लेकर उसकी टैरिफ तय करके दूसरों को दे देंगे । लेकिन जो बिजली का संकट है खेती में, कारखाने में, देश के विकास में, उस शार्टेज को पूरा करने के लिए हमने एडीशनल रिसोर्सेज के लिए एलाऊ किया है ।

अभी-अभी हमारे पांडिचेरी के मित्र ने अपने यहां की बिजली के बारे में कहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपके प्रदेश को बिजली की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे । आपके मुख्य मंत्री हम से मिले थे।

आदरणीय साहू जी ने सवाल किया है कि नादर्न ग्रिड को ईस्टर्न रीजन से जोड़ा जाए । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । हम हिन्दुस्तान के जितने रीजनल जोन्स हैं उनको जोड़ेंगे और सरप्लस एरिया से डिफिसिट एरिया को बिजली देंगे, नेशनल ग्रिड सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं । (व्यवधान)

आदरणीय वीरेन जे० शाह, एम०जी० के० मेनन साहब, अनन्त राम जायसवाल जी, नरेश पुगलिया जी, नारायणस्वामी जी, श्री साहू ने जो हमारे बिल का समर्थन किया है मैं इनको धन्यवाद देता हूं । एक बात आखिर में कहना चाहता हूं शंकर दयाल सिंह जी कि यह राष्ट्रीय मतैक्य का सवाल है । 1988 में श्री राजीव गांधी जी ने एक पालिसी बनाई थी कि प्राइवेट सेक्टर को एलाऊ किया जाए । आदरणीय वी०पी० सिंह जी की सरकार ने पावर मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर राजीव गांधी जी की नीति का प्रतिपादन किया । चन्द्रशेखर जी ने भी फरवरी, 1991 में मुख्य मंत्रियों को बुलाया था और उसमें उन्होंने इसी नीति को स्वीकार किया। वी०पी० सिंह की सरकार ने राजीव गांधी जी की नीति को अपनी सहमति प्रकट की और चन्द्रशेखर जी ने इसी मामले में सब के मतैक्य से अपनी सहमति बनाई और पीछे जो राष्ट्रीय पावर्स मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई उसमें कम्युनिस्ट मंत्रियों ने भी अपनी सहमति प्रकट की । लेकिन कान्फ्रेंस में कुछ, सरकार में कुछ और पार्लियामेंट में कुछ मैं नहीं समझता इससे देश कैसे चलेगा । (व्यवधान) इसलिए जिन मित्रों ने हमारे इस बिल का समर्थन किया है उनको धन्यवाद देते हुए उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसको पास करें ।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : केवल एक बात कह दूं । मंत्री जी ने बहुत व्यावहारिक रूप से कदम उठाया है इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं । लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं कि कोयल-कारो योजना के बारे में आपने मंजूरी के बारे में जिस तरह से घोषणा की उसी तरह से बिहार की 6 बड़ी योजनाएं जो निलम्बित पड़ी हैं आपके पास, मैं समझता हूं उनको भी आप क्लीयर कर सकेंगे जिसके बारे में रजनी रंजन साहू जी ने भी कहा कि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है । (व्यवधान) यह राष्ट्र का मसला है और राष्ट्र के मसले में मैं चाहता हूं, आपके मंत्री ने जो एक बड़े व्यापक ढंग से चीजें रखी हैं मैं उनका स्वागत करते हुए कहना चाहता हूं कि जैसा सदन ने महसूस किया, ठीक है, इस बात को हम जानते हैं कि आप

[श्री शंकर दयाल सिंह]

कहां ले जा रहे हैं, बालानन्दन जी ने ठीक कहा कि आप रिवर्स कर रहे है लेकिन दुनियां की गति है उसमें आप क्या करेंगे। (व्यवधान) लेकिन आपसे मैं इतना अनुरोध जरुर करना चाहूंगा कि निश्चित रुप से बिहार और उत्तर प्रदेश की समस्याओं को आप प्राथमिकता दें क्योंकि सबसे ज्यादा जरुरत वहां है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 14 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

SHRI KALP NATH RAI: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is one statement by the Home Minister.

STATEMENT BY MINISTER

Abduction of five Diamond Merchants on the 15th September 1991.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to apprise the Hon'ble Members of this august House about the abduction of five diamond merchants, namely, S/Shri Milan Parikh, Saunak Parikh, Rajesh Mehta, Anup Kulkarni and Gautam Mehta on 15-9-1991. The Delhi Police have registered a case under section 365 IPC PS Tughlak Road on 16-9-1991 about this incident.

The Delhi Police have reported that during investigation of the case it has come to light that one person calling himself R. Chaudhary had taken residence in Oberoi Hotel, New Delhi on the 17th of August, 1991. He paid Rs. 50,000 as cash and registered himself as a representative of Ferruzzi Finanziaria. The residential address given was Jolly Maker Chamber, Nariman Point, Bombay. Chaudhary began corresponding with a number of firms of Madras, Calcutta and Bombay which deal in diamonds, leather and leather garments. Representatives and partners of these firms came to Delhi on the request of Chaudhary to meet the Italian President of the company which Chaudhary was supposed to represent. Since their meeting with Chaudhary on the 15th September, 1991, S/Shri Milan Parikh, Saunak Parikh, Rajesh Mehta, Anup Kulkarni and Gautam Mehta are missing. Chaudhary himself was last seen in Oberoi Hotel at about 7.00 P.M. on the 15th of September, 1991. Search of his room and his locker has ben carried out but no further details of his identity are forthcoming. He has left behind some clothes and toiletry articles and some papers.

Investigation also shows that during the period Chaudhary stayed in the Oberoi, he made a number of telephone calls to Calcutta, Bombay Lucknow, Kanpur, Madras and Karachi. Some local calls were also made by him. The names and the addresses of the subscribers are being traced. Enquiries and investigation have also revealed that he was using hired self-driven vehicles by